The Hindu- 02- April-2023

Cauvery-Vaigai-Gundar link work speeded up after DMK came to power, says Duraimurugan

The Hindu Bureau
CHENNAI

The Tamil Nadu government is keen on swiftly completing the Cauvery-Vaigai-Gundar linking project, Minister for Water Resources Duraimurugan said in the Assembly on Saturday.

Refuting concerns expressed by the AIADMK, through a calling attention motion, that the project had slowed down after the DMK came to power, Mr. Duraimurugan said land acquisition and canal digging had, in fact, been speeded up in the past two years.

Though an allocation of ₹600 crore was made in 2020 towards land acquisition by the previous AIADMK government, only ₹34.31 crore was spent, and 71.6 acres was acquired, he said. The unspent money went back to the government that year. In contrast, the present government had allocated ₹312 crore in the past two years and acquired 698.97 acres.

Minister for Water Resources Duraimurugan said land acquisition and canal digging works had been speeded up in the past two years. FILE PHOTO

Moreover, the DMK government had made a provision to retain the unspent money in a deposit for further use towards land acquisition instead of returning it by the end of a financial year.

Pointing out that no work of canal digging had happened in 2020-21 during the AIADMK rule, he said the present government had allocated ₹177.9 crore in the past two years and completed 64% of the targeted work. A further allocation of ₹554.17 crore towards land acquisition and ₹111.52 crore towards digging a canal had been made for 2023-24, the Minister noted. Earlier, AIADMK MLA C. Vijayabaskar from Viralimalai, who moved the motion, said that though the project was a dream of many Chief Ministers, it was former Chief Minister Edappadi K. Palaniswami who allocated funds and commenced the work. Quipping that Mr. Vijayabaskar was trying to make it out that only the previous AIADMK government had done all the work, Mr. Duraimurugan said the construction of the barrage at Mayanur for the project was launched during the DMK rule in 2009.

'Expedite project'

CPI(M) MLA M. Chinnadurai, who spoke on the motion, appealed to the government to expedite the project as it would benefit farmers in seven districts.

Amar Ujala- 02- April-2023

निगम बोध घाट के पास की जा रही यमुना नदी की सफाई। एजेंसी

चिंता : यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर महापंचायत

अमर उजाला ब्यूरो

करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी राजधानी में यमुना नाले की तरह बह रही है

नई दिल्ली। यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर रविवार को मुंडका विधानसभा क्षेत्र के हिरण कूदना ग्राम में महापंचायत की गई। इसमें कहा गया कि पिछले आठ साल में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी यमुना नाले की तरह बह रही है।

केंद्र व दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए कि धनराशि कहां गई। इसके विरोध में चार जून को एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर लोग अपना विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. नरेश कुमार ने कहा है कि दिल्ली और केंद्र की भाजपा सरकार ने यमुना की सफाई के नाम पर 2013 से 23 अगस्त 2021 तक 653.86 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन अब तक इसकी हालत पहले जैसी है। ऐसे में दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने हाल में 6100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 के चुनावी घोषणा पत्र कहा था कि यमुना नदी को लंदन की टेम्स नदी बना देंगे, लेकिन आज यहां प्रदूषण की वजहस से लोग छठ पर्व करने से भी परहेज करते हैं।

Rajasthan Patrika- 02- April-2023

अन्नाद्रमुक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जल संसाधन मंत्री दुरै मुरुगन का जवाब

कावेरी-वैगै-गुंटारू लिंक परियोजना डीएमके सरकार पूरा करेगी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चेन्नई. दक्षिणी जिलों में पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण कावेरी-वैगै-गुंटारू लिंक परियोजना को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में शनिवार को गरम बहस हुई। प्रमुख प्रतिपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस मसले को उठाया तो जल संसाधन मंत्री दुरै मुरुगन ने कहा कि परियोजना का दो तिहाई कार्य पूरा हो चुका है और डीएमके शासन में ही इस योजना को खुला घोषित कर दिया जाएगा।

जमीन अधिग्रहण का कार्य मंदा

विधानसभा में शून्य काल में प्रस्ताव पेश करते हुए अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री विजयभास्कर ने कहा कि कावेरी-वैगै-गुंटारू लिंकेज परियोजना पूर्व सीएम कामराज के जमाने की है जिसे समयबद्ध तरीके से उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा लागू किया जाना चाहिऐ था। विपक्ष के मौजूदा नेता और पूर्व सीएम एडपाड़ी के. पलनीस्वामी ने इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए बजट में 700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लेकिन वर्तमान में भूमि अधिग्रहण और नहर काटने का काम धीरे-धीरे चल रहा है।

मंत्री का जवाब

इसका जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सदस्य गलत जानकारी दे रहे हैं कि यह योजना पूर्व सीएम ईपीएस लेकर आए। पूर्व सीएम करुणानिधि ने ही सबसे पहले कावेरी गुंटारू लिंकेज परियोजना के बारे में सोचा और धन आवंटित किया। पिछली सरकार के वक्त इस परियोजना के लिए केवल 71 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और डीएमके के सत्ता में आने के बाद 600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है। पिछली सरकार में भूमि अधिग्रहण के साथ ही कार्य बंद हो गया था। हमने सत्ता में आने के बाद कार्य शुरू कराया। नहर काटने का 64 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। हम यकीन दिलाते हैं कि कावेरी गुंटारू लिंकेज परियोजना मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के शासन के दौरान निश्चित रूप से पूरा की जाएगी।

Hindustan- 02- April-2023

पहल | जल प्रलय से निपटने के लिए अनोखा इंतजाम, जमीन के 42 मीटर नीचे पानी को जमा किया जाता है

जमीन में सुरंग बनाकर बाढ़ रोक रहा जापान

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो।
जापान ने बाढ़ से निपटने के लिए अनोखी तरकीब अपनाई है। जमीन के अंदर टनल और गुफा बनाकर जापान बाढ़ को रोक रहा है। जमीन के नीचे 42 मीटर तक भूमिगत सुरंगें हैं जहां अस्थायी तौर पर बारिश के पानी को जमा किया जाता है। ये टनल 14 मंजिली इमारत जितनी गहरी हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में यह टनल राजधानी को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया है।

जलवायु परिवर्तन ने हाल के वर्षों में जापान को काफी प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन ने जापान में बाढ़ के खतरों को काफी बढ़ा दिया है, जिससे तूफान और भारी वर्षा के लंबे समय तक होने की संभावना बढ़ गई है। जलवायु में परिवर्तन के कारण औसत वार्षिक वर्षा में वृद्धि हुई है। टोक्यो में औसत वार्षिक तापमान भी बढ़ा है। जापान में ये परिवर्तन पहले से ही वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जापान में तूफान और मूसलाधार बारिश के गंभीर होने की आशंका है।

2030 तक जलाशय मंडारण क्षमता 3.6 लाख क्यूबिक मीटर करने का लक्ष्य

02 ट्रिलियन येन की क्षति जापान को 2019 में हुई बाढ़ से

भारत में किए जा रहे उपाय

- देश में 333 पूर्वानुमान स्टेशनों से केंद्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान जारी होता है, ये 25 राज्यों की 20 प्रमुख नदियों को कवर करते हैं।
- नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार बाढ़ प्रबंधन योजना को 2026 तक जारी रखा जाएगा।
- इसमें जल मौसम से संबंधित आंकड़े जुटाना, बाढ़ पूर्वानुमान के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जाएंगे
- फ्लैश फ्लड के अनुनान के लिए मॉडल आधारित प्रणाली का विकास किया जाएगा
- सभी जलाशयों के स्तर को मापा जाएगा, वर्षा की प्रवृत्ति और बदलती मांग में परिवर्तन को भी अपडेट किया जाना है।

जापान में बाढ़ से नुकसान

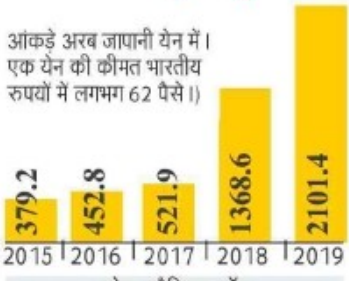

(स्रोत: स्टैटिस्टा.कॉम)

खाली समय में पर्यटन के लिए खुला रहता है टनल

बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए इस टनल की खासियत यह है कि जब इसका उपयोग नहीं होता है तो इसे पर्यटन के लिए खोल दिया जाता है। सैतामा प्रान्त में मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल है।